

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO.03
ANSWERED ON 02.02.2024

RAILWAY INFRASTRUCTURE IN TAMIL NADU

*3. SHRI R. GIRIRAJAN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

- (a) whether income through Southern Railway is being pooled back to Railway projects in Tamil Nadu and if so, the details thereof;
- (b) whether Government plans for construction of new Road Over Bridges (ROB), Rail Under-Bridges (RUB), Foot Over Bridges (FOB), Escalators and other infrastructure facilities like installation of CCTVs and Digital Rail Information displays, Multi-level Parking facilities in Tamil Nadu and if so, details thereof and the total amount allocated and disbursed for the same;
- (c) whether Government has identified railway infrastructure needs of Tamil Nadu, and if so details thereof, Railway Division-wise; and
- (d) the total funds earmarked for the same?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND
ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (d) OF STARRED QUESTION NO. 03 BY SHRI R. GIRIRAJAN ANSWERED IN RAJYA SABHA ON 02.02.2024 REGARDING RAILWAY INFRASTRUCTURE IN TAMIL NADU

(a) In 2022-23, total revenue generated by Southern Railway (SR) was ₹ 9,966.69 cr. against expenditure of ₹ 15,345.69 cr., implying thereby that Ministry of Railways has supported SR's additional expenditure over its revenue by ₹ 5,379 cr. Additionally, SR's net Capital expenditure in 2022-23 from Gross Budgetary Support etc. for creation of assets like New lines, Doubling, Electrification, Station Development, Customer Amenities and other developmental works was ₹ 7,526.84 cr.

(b) to (d) Railway Infrastructure Projects are taken up on the basis of remunerativeness, last mile connectivity, missing links and alternate routes, augmentation of congested/saturated lines, socio-economic considerations etc. depending upon liabilities of ongoing projects, overall availability of funds and competing demands. Sanction of Railway infrastructure projects in areas which are not connected by Railway network including coal connectivity projects is a continuous and ongoing process of Indian Railways. The Railway Infrastructure projects are sanctioned Zonal Railway wise and not State wise/UT wise as the Railways' projects may span across various state boundaries.

Budget allocation for Infrastructure and safety works, falling fully/partly in the State of Tamil Nadu has been increased to ₹ 6,080 crore this year which is nearly seven times of the average budget allocation of ₹ 879 crore from 2009-14.

Tamil Nadu state is covered by Southern Railway (SR), South Central Railway (SCR) and South Western Railway (SWR). As on 01.04.23, 23 projects (09 new line, 03 Gauge conversion and 11 doubling) of total length of 2,848 Km and costing ₹ 35,580 crore falling fully/partly in the State of Tamil Nadu are at planning/approval/construction stage. These include: -

- I. 9 New Line projects covering total length of 871 km at a cost of ₹ 14,682 crore.
- II. 3 Gauge Conversion projects covering total length of 748 km at a cost of ₹ 5,224 crore
- III. 11 Doubling projects covering total length of 1,229 km at a cost of ₹ 15,674 crore.

Though fund allocation has increased manifold but pace of execution of project is dependent on expeditious land acquisition. Railway acquires the land through State Government. State Government assesses the compensation amount and advises to Railway. On receipt of demand from State Government, Railway deposits compensation amount with concerned District Land Acquisition Authority. Execution of important infrastructure projects falling fully/partly in the State of Tamil Nadu is held up due to delay in land acquisition and only about 624 Ha land has been acquired out of total requirement of about 1832 Ha. Railway had initiated efforts for acquisition of land but could not succeed in acquiring land for projects.

Augmentation of Passenger Amenities at Railway stations is a continuous process. Ministry of Railways has launched 'Amrit Bharat Station scheme' for development of Stations on Indian Railways. So far, 1318 number of railway stations including 77 railway stations in the State of Tamil Nadu have been identified for development/redevelopment under this scheme.

This scheme envisages development of stations on a continuous basis with a long term approach. It involves preparation of Master Plans and their implementation in phases to improve the amenities at the stations like improvement of station access, circulating areas, waiting halls, toilets, lift/escalators as necessary, cleanliness, free Wi-Fi, kiosks for local products through schemes like 'One Station One Product', better passenger information systems, executive lounges, nominated spaces for business meetings, landscaping etc. keeping in view the necessity at each such station.

The scheme also envisages improvement of building, integrating the station with both sides of the city, multimodal integration, amenities for Divyangjans, sustainable and environment friendly solutions, provision of ballast less tracks, 'Roof Plazas' as per necessity, phasing and feasibility and creation of city centres at the station in the long term. In addition to the above, since 01.04.2014 (till December 2023), 542 Road Under Bridges (RUBs) and 134 Road Over Bridges (ROBs) have been completed in Tamil Nadu. Further, a total of 129 ROBs and 100 RUBs are under planning/execution stage.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

राज्य सभा
02.02.2024 के
तारांकित प्रश्न सं. 3 का उत्तर

तमिलनाडु की रेलवे अवसंरचना

*3. श्री आर. गिरिराजन:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या दक्षिण रेलवे से प्राप्त होने वाली आय का तमिलनाडु की रेल परियोजनाओं हेतु फिर से प्रयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार की तमिलनाडु में नए उपरि सड़क पुलों (आरओबी), रेल अंडर ब्रिजों (आरयूबी), फुट ओवर ब्रिजों (एफओबी), स्वचालित सीढ़ियों और सीसीटीवी तथा डिजीटल रेल सूचना प्रदर्शन बोर्डों की स्थापना, बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाओं जैसी अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित और संवितरित की गई है;
- (ग) क्या सरकार ने तमिलनाडु की रेल अवसंरचना संबंधी आवश्यकताओं का अभिनिर्धारण किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी रेल मंडल-वार ब्यौरा क्या है; और
- (घ) इसके लिए कुल कितनी निधि निर्धारित की गई है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

तमिलनाडु की रेलवे अवसंरचना के संबंध में दिनांक 02.02.2024 को राज्य सभा में श्री आर. गिरिराजन के तारांकित प्रश्न सं. 03 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण

(क) वर्ष 2022-23 में, दक्षिण रेल द्वारा प्रोद्भूत कुल राजस्व ₹9,966.69 करोड़ था जबकि व्यय ₹15,345.69 करोड़ था, जिसका अर्थ है कि दक्षिण रेल के राजस्व की तुलना में इसके अतिरिक्त व्यय के लिए रेल मंत्रालय ने ₹5,379 करोड़ की सहायता की थी। इसके अलावा, वर्ष 2022-23 में नई लाइनों, दोहरीकरण, विद्युतीकरण, स्टेशन विकास, ग्राहक सुविधाओं आदि जैसी परिसंपत्तियों के निर्माण और अन्य विकास कार्यों के लिए सकल बजट सहायता आदि से दक्षिण रेल का शुद्ध पूंजीगत व्यय ₹7,526.84 करोड़ था।

(ख) से (घ) रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, अंतिम मील संपर्क, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों आदि के आधार पर शुरू किया जाता है जो चालू परियोजनाओं की देयताओं, धन की समग्र उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी मांगों पर निर्भर करता है। भारतीय रेल में कोयला संपर्क परियोजनाओं सहित रेल नेटवर्क से जुड़े क्षेत्रों में रेल अवसंरचना परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत और चलायमान प्रक्रिया है। रेल अवसंरचना परियोजनाएं क्षेत्रीय रेल-वार स्वीकृत की जाती हैं, न कि राज्य-वार/केंद्र-शासित प्रदेश-वार क्योंकि रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्य सीमाओं के आर-पार सर्वत्र फैली हो सकती हैं।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित अवसंरचना और संरक्षा परियोजनाओं के लिए बजट आवंटन इस वर्ष बढ़ाकर ₹6,080 करोड़ कर दिया गया है, जो कि 2009-14 के ₹879 करोड़ के बजट आवंटन का लगभग सात गुना है।

तमिलनाडु राज्य को दक्षिण रेल, दक्षिण मध्य रेल और दक्षिण पश्चिम रेल द्वारा सेवा प्रदान की जाती है। दिनांक 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित ₹35,580 करोड़ की लागत पर कुल 2,848 किलोमीटर लंबाई की 23 रेल परियोजनाएं (09 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन तथा 11 दोहरीकरण) योजना बनाने/अनुमोदन/निर्माण के चरण में थीं। इनमें शामिल हैं:-

- I. ₹14,682 करोड़ की लागत पर कुल 871 किलोमीटर लंबाई की 9 नई लाइन परियोजनाएं।
- II. ₹5,224 करोड़ की लागत पर कुल 748 किलोमीटर लंबाई की 3 आमान परिवर्तन परियोजनाएं।
- III. ₹15,674 करोड़ की लागत पर कुल 1,229 किलोमीटर लंबाई की 11 दोहरीकरण परियोजनाएं।

हालांकि बजट आबंटन कई गुना बढ़ाया गया है लेकिन परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया जाता है। राज्य सरकार मुआवजा राशि का निर्धारण करती है और रेलवे को सूचित करती है। राज्य सरकार से मांग प्राप्त होने पर रेलवे द्वारा संबंधित जिला भूमि अधिग्रहण प्राधिकरण के पास मुआवजा धनराशि जमा करवाई जाती है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः स्थित महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है और लगभग कुल 1832 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता में से लगभग केवल 624 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए प्रयास शुरू किए गए थे लेकिन परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने में सफल नहीं हो सकी थी।

रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं का संवर्धन एक सतत प्रक्रिया है। रेल मंत्रालय द्वारा भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए 'अमृत भारत स्टेशन योजना' प्रारंभ की गई है। अभी तक इस योजना के अंतर्गत विकास/पुनर्विकास के लिए तमिलनाडु राज्य में 77 रेलवे स्टेशनों सहित 1318 रेलवे स्टेशनों का अभिनिर्धारण किया गया है।

इस योजना में दीर्घकालिक विधि के साथ सतत आधार पर रेलवे स्टेशनों के विकास की संकल्पना की गई है। इसमें प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए मास्टर प्लान तैयार करना और रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं जैसे स्टेशन तक पहुंच, परिचलन क्षेत्र, प्रतीक्षालय, शौचालय में यथा आवश्यक सुधार; आवश्यकता के अनुसार लिफ्ट/एस्केलेटर; स्वच्छता; मुफ्त वाई-फाई; 'वन स्टेशन वन प्रोडक्ट' जैसी योजनाओं द्वारा स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क; बेहतर यात्री सूचना प्रणाली; एकजीक्यूटिव लाउंज; व्यावसायिक बैठकों के लिए नामोदिष्ट स्थान; भूदृश्य निर्माण; आदि में सुधार लाने के लिए उनका चरणबद्ध कार्यान्वयन शामिल है।

इस योजना में लंबी अवधि के दौरान स्टेशन भवन में सुधार; रेलवे स्टेशन का शहर की दोनों तरफ के साथ एकीकरण; मल्टी-मोडाल एकीकरण; दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं; दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान; गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था; आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार 'रूप प्लाजा'; और रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टर्स के निर्माण की संकल्पना की गई है। उपरोक्त के अलावा, 01.04.2014 से (दिसंबर 2023 तक) तमिलनाडु में 542 रोड अंडर ब्रिज और 134 रोड ओवर ब्रिज पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा, कुल 129 रोड ओवर ब्रिज और 100 रोड अंडर ब्रिज योजना बनाने/निष्पादन के चरण में हैं।

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, I thank the hon. Minister for his reply.

Sir, the budgeted allocation for the Southern Railway, particularly for railway projects and passenger amenities in Tamil Nadu is very much wanting for more than ten years. In his reply, the hon. Minister himself has confirmed that the Railways sanctioned an amount of Rs. 879 crores between 2009 and 2014.

So, I would like to know from the hon. Minister the amount allocated to railway projects in Tamil Nadu from 2014 to 2022, income generated through passengers, freight traffic and other source during the last ten years i.e., since 2014, steps to be taken by the Government to complete several railway projects in Tamil Nadu pending since 2008 and the list of projects, actually, pending.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, be brief in your supplementary.

SHRI R. GIRIRAJAN: I would like to know the exact status of long-pending railway projects from the hon. Minister.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you. Be brief in your question. I expect reply will also be brief.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, रेल परियोजनाएँ राज्यवार नहीं ज़ोनवार होती हैं। तमिलनाडु राज्य दक्षिण, दक्षिण-मध्य और दक्षिण-पश्चिम, इन तीन ज़ोन्स को कवर करता है। ये परियोजनाएँ केवल तमिलनाडु के लिए नहीं हैं, बल्कि ये ज़ोनवार चलती हैं, लेकिन तमिलनाडु में अभी काफी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स स्थापित किए जा रहे हैं। वहाँ पर ढांचागत परियोजनाओं और संरक्षा के लिए वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक औसतन 879 करोड़ प्रति वर्ष बजट दिया गया था, लेकिन अब वर्ष 2023-24 में वर्ष 2009-14 से लगभग सात गुना ज्यादा, यानी 6,080 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। यानी, वर्ष 2009-14 में तमिलनाडु का जो बजट औसतन 879 करोड़ प्रति वर्ष का था, वह आज वर्ष 2023-24 में 6,080 करोड़ रुपये का हो गया है। वहाँ पर अभी जो परियोजनाएँ चल रही हैं, उनमें नौ परियोजनाएँ नई लाइंस की हैं, ग्यारह दोहरीकरण और तीन गेज परिवर्तन के लिए चल रही हैं। महोदय, वहाँ जो नई लाइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी कुल लम्बाई 871 किलोमीटर्स की है और उनकी लागत 14,682 करोड़ रुपये की है। इसी तरह, तमिलनाडु में अभी रेलवे लाइंस का गेज परिवर्तन 748 किलोमीटर्स और दोहरीकरण 1,229 किलोमीटर्स का चल रहा है।

SHRI R. GIRIRAJAN: Sir, under Amrit Bharat Station Scheme, Southern Railway plans to complete upgradation of 90 railway stations this year and 15 stations in Chennai region. There is an urgent need for fourth terminal in Chennai. There is a plenty of vacant land belonging to Railways available around Perambur where the ICF

is located. Sir, my supplementary to the hon. Minister is whether the Railways would come forward to utilize available vacant land belonging to Railways around Perambur to establish a much needed fourth railway terminal in Chennai to avoid congestion at Chennai Central and Chennai Egmore. Thank you.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, रेल विभाग की दृष्टि से तमिलनाडु एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है। वहाँ लगभग 77 स्टेशंस 'अमृत भारत स्टेशन स्कीम' के अंतर्गत लिए गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो खाली पड़ी जमीनें हैं, उनका उपयोग हो रहा है। क्षमता की दृष्टि से आज सबसे बड़ी coach factory ICF पेरम्बुर, तमिलनाडु में है, जहां वर्ष 1955 में उत्पादन शुरू हुआ था, जब वहाँ 1,000 से भी कम डिब्बे प्रति वर्ष बनते थे। वर्ष 2019-20 में हमने वहाँ की ICF में 4,166 डिब्बे बनाए, वर्ष 2022-2023 में 2,702 बनाए और वर्ष 2023-24 में 3,241 डिब्बे बनाने का हमारा लक्ष्य है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर जितनी जगह है, उसका हम पूरा उपयोग कर रहे हैं।

DR. M. THAMBIDURAI: Mr. Deputy Chairman, Sir, through you, I would like to know from the hon. Minister the present status of the long-pending railway project for laying new railway line between Jolarpettai and Bengaluru via Krishnagiri and Hosur. The Ministry of Defence has declared Hosur and Krishnagiri as 'defence corridor'. Therefore, this line is very, very important. Discussion on this line has been going on for thirty-five years. What is the present position of connecting this line?

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: उपसभापति महोदय, वहां 4 परियोजनाएं चल रही हैं। मदुरई-बोडिनायक्कनूर, रामेश्वरम-धनुषकोडी परियोजना, तिंडीवनम-जिंजी-तिरुवन्नामलई, मोरापुर धर्मापुरी रेल परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन मदुरई-वेडासंदूर कमीशन हो गया है और उसकी लागत 593 करोड़ रुपये है।...(व्यवधान)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please let him reply. ...*(Interruptions)*...

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: महोदय, तमिलनाडु सरकार ने रामेश्वरम धनुषकोडी परियोजना हटाने का आग्रह किया है।

श्री उपसभापति : माननीय मंत्री जी, डा. मु. तंबी दुरै जी जिस प्रश्न के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आपके पास अभी उत्तर न हो तो आप बाद में भी बता सकते हैं। Dr. John Brittas, you have a question. Please go to your seat. ...*(Interruptions)*... Next, Dr. Fauzia Khan.

डा. फौजिया खान: सर, मैं महिला होने के नाते माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब हम रेल प्रवास करते हैं, तो टॉयलेट्स की बहुत तकलीफ होती है। ट्रेन्स में इतने गंदे

टॉयलेट्स होते हैं कि जो most modern toilets हैं, वे भी पूरे फुल हो कर खराब हो जाते हैं। महिलाओं को ट्रेन्स में अच्छे और साफ-सुथरे टॉयलेट्स मिलें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? †**डाक्टर فوزیه خان:** سر میں مہیلا ہونے کے ناتے مانیئے منتری جی سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ہم ریل پر اس کرتے ہیں، تو ٹائلیٹ کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ٹرینس میں اتنے گندے ٹائلیٹس ہوتے ہیں کہ جو most modern toilets ہیں، وہ بھی پورے فل ہو کر خراب ہو جاتے ہیں۔ مہیلاؤں کو ٹرینس میں اچھے اور صاف ستھرے ٹائلیٹس ملیں، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: आदरणीय उपसभापति महोदय, रेल में जो टॉयलेट्स बनाए हैं, उनको साफ-सुथरा रखने के लिए सरकार पूरी कोशिश करती है। अगर हमारे पास ऐसी कोई शिकायत आती है, तो मैं उसको दूर करूंगा।

DR. JOHN BRITTAS: Mr. Deputy Chairman, Sir, the hon. Minister has spoken about the investment that is being done in the Southern Railway. As you would appreciate, Kerala is also a part of the Southern Railway. And, Vande Bharat trains, which are plying in Kerala have the highest occupancy rate in the country. ...*(Interruptions)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Put your question, please. ...*(Interruptions)*...

DR. JOHN BRITTAS: It has justified the demand for a semi-high-speed railway because of the enhanced demand. So, in this context, I would specifically ask the hon. Minister whether he will consider the K-Rail Project, submitted by the Kerala Government to the Railway Minister.

श्री दानवे रावसाहेब दादाराव: आदरणीय उपसभापति महोदय, अपने देश में अभी वंदे भारत ट्रेन्स शुरू की गई हैं, हर ज़ोन में उसकी मांग बढ़ती जा रही है। आज हम 41 ट्रेन्स चला रहे हैं और जैसे-जैसे ट्रेन्स की उपलब्धता होगी, वैसे-वैसे हम देंगे। ...*(व्यवधान)*...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: There are other methods also ...*(Interruptions)*... माननीय सदस्य का जो सवाल है, माननीय मंत्री जी, आप उसका उत्तर पता करके माननीय सदस्य को बुलाकर उन्हें बता दें।

श्री उपसभापति: प्रश्न संख्या-4, श्री ईरण कडाडी

† Transliteration in Urdu script.